Times of India, Bhopal, 08/10/2025
Page No: 4, Size: 15.74cm × 13.81cm

# NHRC steps in after child deaths in Jabalpur dist

**Bhopal**: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of an incident where two children, aged 8 and 10 years, died due to electrocution while playing inside a Durga Puja pandal in Jabalpur district. The commission on Monday observed that this raises serious issues of human rights violations. Therefore, it has issued notices to the chief secretary, govt of MP, and the superintendent of police, Jabalpur, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

In a different incident, NHRC took suo motu cognisance of a case where three children suffering from pneumonia were branded with a hot iron rod by a faith healer in Jhabua district. TNN

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

**Hindustan, Kaushambi District, 08/10/2025**

**Page No: 2, Size: 12.14cm × 4.26cm**

# आज जनसुनवाई करेंगे आयोग के सदस्य

मंझनपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियांक कानूनगो आठ अक्तूबर को दोपहर 12 बजे मंझनपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वह दो बजे तक विकास भवन स्थित सरस हाल में आमजन एवं स्थानीय सिलिकोसिस रोगियों की जनसुनवाई करेंगे। अपरान्ह दो बजे से उदयन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद शाम चार बजे जनपद से प्रस्थान करेंगे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

**Nai Duniya, Raipur, 08/10/2025**
Page No: 9, Size: 12.33cm × 18.07cm

# समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने से पहाड़ी कोरवा युवक की मौत

**नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर :** सड़क दुर्घटना में घायल हुए पहाड़ी कोरवा युवक गुड्डू कोरवा की मौत पर मंगलवार को मेडिकल कालेज अस्पताल में शव रखकर विरोध-प्रदर्शन किया गया।

परिवारवालों ने समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने के चलते मौत होने का आरोप लगाया। मृतक के स्वजन के साथ ही कांग्रेसियों ने भी शव को मेडिकल कालेज अस्पताल परिसर में रखकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि एंबुलेंस राज्यपाल रमेन डेका के प्रोटोकाल में लगी हुई थी। इस कारण समय पर एंबुलेंस नहीं मिल सकी।

ग्राम ककना (मदेश्वरपुर) के रहने वाले गुड्डू कोरवा (34) चार अक्टूबर को अपने साथी बजल साय के साथ ग्राम घटगांव से लौटते समय मुरूम के ढेर से बाइक टकरा गई। हादसे में गुड्डू के सिर पर गंभीर चोट आई। उसे अंबिकापुर मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रविवार दोपहर रायपुर रेफर कर दिया।

**रायपुर पहुंचने से पहले ही हो गई मौतः** गुड्डू कोरवा को सोमवार शाम रायपुर भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रायपुर पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि स्वजन को शव वाहन तक उपलब्ध नहीं कराया गया। दावा किया गया किराए पर निजी वाहन से शव को अंबिकापुर वापस लाया गया। रायपुर में शव का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था।

**प्रोटोकाल ड्यूटी से लौटते ही एंबुलेंस से भेजा गयाः** इस मामले को लेकर मेडिकल कालेज अस्पताल के अधीक्षक डाक्टर आरसी आर्या ने कहा कि मरीज के सिर पर गंभीर चोट थी। अस्पताल में वेंटिलेटर एंबुलेंस है, जो प्रोटोकाल ड्यूटी में थी। जैसे ही एंबुलेंस लौटी, मरीज को रायपुर भेज दिया गया था।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

**Dainik Jagran, Banda, 08/10/2025**

Page No: 2, Size: 18.44cm × 20.56cm

# क्रशर में काम करने वाले बच्चों का छात्रावास में कराएं दाखिला

## मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने ठेकेदारों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा

बैठक करते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो (बीच में) • जागरण

**जागरण संवाददाता, चित्रकूट** : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मानवाधिकार एवं समावेशी विकास की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की। सबसे गंभीर और संवेदनशील पहलू उस समय सामने आया, जब कानूनगो ने क्रशर इकाइयों में कार्यरत बच्चों की जानकारी मांगी। सदस्य ने सहायक श्रम आयुक्त से सवाल किया कि जिले में कितने क्रशर संचालित हो रहे हैं और क्या वहां नाबालिग बच्चों से कार्य कराया जा रहा है। जवाब मिलने पर उन्होंने स्पष्ट नाराजगी जताई और सख्त लहजे में निर्देश दिया कि ऐसे सभी बच्चों को तत्काल चिह्नित कर सरकारी छात्रावासों में दाखिला दिलाया जाए।

उन्होंने कहा कि यदि कोई ठेकेदार बच्चों से मजदूरी कराते हुए मिलता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल एफआइआर दर्ज कराई जाए। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो यह मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने कहा, बाल अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बच्चों से मजदूरी कराना गंभीर अपराध है। सदस्य ने बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया तेज करने और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए निगरानी तंत्र को सशक्त करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने श्रम विभाग और समाज कल्याण विभाग को समन्वय कर कार्य योजना बनाने को कहा। प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने आयोग सदस्य को आश्वासन दिया कि सभी विभाग समन्वय बनाकर दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करेंगे। एसपी अरुण कुमार सिंह, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) उमेश चंद्र निगम, एएसपी सतपाल सिंह, एसडीएम कर्वी पूजा साहू, डीसी एनआरएलएम ओपी मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी वैभव त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी पीडी विश्वकर्मा, सीएमओ डा. भूपेश द्विवेदी, डीआईओएस रविशंकर, बीएसए बीके शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता रही।

**Aaj, Patna, 08/10/2025**
Page No: 9, Size: 16.80cm × 10.27cm

# कोल्डरिफ सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत

नयी दिल्ली (एजेंसी)। भारत में कफ सिरप पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद कई राज्यों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने की बात कही.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर उन्हें दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के आरोपों की जांच करने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है. याचिकाकर्ता ने दवाओं के निर्माण, परीक्षण और वितरण की व्यवस्था की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की है. बच्चों की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग याचिका में की गई है.महाराष्ट्र एफडीए ने एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है कि रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ कफ सिरप में सुरक्षित सीमा से अधिक विषाक्त डायएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) मौजूद है. बिक्री, वितरण या उपयोग पर रोक है और लाइसेंसधारियों को किसी भी स्टॉक की तुरंत सूचना देनी होगी.इसे लेकर तमिलनाडु सरकार ने 44 पेज

की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी श्रीसेन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर काचीपुरम में 39 गंभीर और 325 बड़ी खामियां निकली.रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी किसी भी स्तर पर जीएमपी (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज) के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही थी. कंपनी फार्मास्यूटिकल ग्रेड के बजाय गैर-फार्मास्यूटिकल ग्रेड प्रोपलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कफ सिरप निर्माण में कर रही थी.यह केमिकल बिना इनवॉइस अलग-अलग तिथियों पर 50-50 किलो के पैक में खरीदा गया. भुगतान नकद या गूगल-पे के माध्यम से किया गया था.खरीदे गए प्रोपलीन ग्लाइकोल में डायथिलीन ग्लाइकोल 48.6 परसेंट और एथिलीन ग्लाइकोल पाए गए जो बेहद विषैले तत्व हैं और इंसानी शरीर के लिए जानलेवा साबित होते हैं. दवाइयों को गंदगी, कीचड़ और कीड़ों से भरे माहौल में बनाया और संग्रहित किया जा रहा था यहां ड्रेन सिस्टम नहीं था, जिससे चूहे, कीड़े-मकौड़े अंदर घुस रहे थे. तमिलनाडु सरकार ने फैक्ट्री का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैपंजाब में भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप को बैन कर दिया गया है. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब ने मध्य प्रदेश में हुई मौतों को देखते फैसला लिया है. छिंदवाड़ा में कफ सिरप मामले में आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को 9 अगस्त तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है. मध्य प्रदेश में कफ सिरफ से 21 मौतें हुई हैं, जिसमें से छिंदवाड़ा में 18, बैतूल में 2, पंढुरना में 1 बच्चे की मौत हुई.

The Hans India

## PIL in SC over deaths of children linked to contaminated cough syrup

https://www.thehansindia.com/amp/news/national/pil-in-sc-over-deaths-of-children-linked-to-contaminated-cough-syrup-1012540

The Hans India | Update: 2025-10-07 12:30 IST

A public interest litigation (PIL) has been filed before the Supreme Court seeking urgent judicial intervention to address the deaths of children allegedly caused by the consumption of contaminated cough syrup in Madhya Pradesh and Maharashtra.

At least 14 children have died since early September, with most of the cases reported from Nagpur in Maharashtra and Chhindwara in Madhya Pradesh.

The PIL, filed by advocate Vishal Tiwari, claimed that laboratory tests conducted by the Madhya Pradesh government confirmed the presence of Diethylene Glycol (DEG) -- a toxic industrial solvent prohibited for pharmaceutical use -- in 'Coldrif Cough Syrup' manufactured by Tamil Nadu’s Sresan Pharma Pvt. Ltd.

The initial cases were reported from Madhya Pradesh’s Chhindwara district in early September, and within days, the death toll mounted as similar cases emerged from Nagpur, Maharashtra.

“Despite the catastrophic findings, the Union Government and the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) allegedly failed to issue an immediate nationwide recall or ban, permitting the continued circulation of potentially poisonous medicines across States,” the plea stated.

It drew parallels with the Gambia and Uzbekistan incidents, where DEG-contaminated Indian syrups were linked to over 90 child deaths abroad.

“This is not a tragedy of chance but of negligence, apathy, and regulatory failure -- an institutional rot that allows counterfeit and adulterated drugs to enter the public market unchecked,” the PIL stated.

The plea has sought the constitution of a National Judicial Commission or Expert Committee, headed by a retired Supreme Court judge, to conduct a comprehensive inquiry into the manufacture, regulation, testing and distribution of contaminated syrups and to recommend systemic drug-safety reforms.

Further, it seeks a Central Bureau of Investigation (CBI) probe into the deaths of children across states, under the supervision of a former apex court judge.

The PIL also urged the top court to transfer all pending FIRs related to the deaths to the CBI to ensure a uniform and independent investigation.

Another prayer is for immediate recall, seizure and prohibition of all batches of Coldrif Cough Syrup and other related formulations manufactured by Sresan Pharma Pvt. Ltd.,

until independent NABL-accredited laboratories issue toxicological clearance and verification of safety.

On Monday, the National Human Rights Commission (NHRC) issued notices to the Principal Secretaries of the Health Departments of Madhya Pradesh and Rajasthan on a complaint alleging serious lapses in drug safety and regulatory mechanisms that led to the tragedy.

The apex human rights body has directed the Drugs Controller General of India (DCGI), Central Drugs Standard Control Organisation, Union Ministry of Health and Family Welfare, to initiate a comprehensive investigation into the supply chain of the alleged spurious drugs, apart from instructing all regional labs in the concerned states to collect and test samples.

“The authority is also directed to order all the Chief Drugs Controllers in the concerned states to process immediately the banning of the spurious drugs and submit reports,” the NHRC said.

Dainik Jagran MP CG

# NHRC issues notices to governments: Demands investigation into Coldriff syrup case; orders state labs to send reports

https://english.dainikjagranmpcg.com/national/nhrc-issues-notices-to-governments-demands-investigation-into-coldriff-syrup/article-6012

Digital Desk | On 07 Oct 2025

NHRC issues notices to Rajasthan, MP-UP governments; Demanded investigation into Coldriff syrup case; orders state labs to collect samples and send reports

The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday issued notices to the governments of Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh, directing them to investigate the deaths of children amid cough syrup row.

It is also directed an immediate ban on the sale of fake medicines. Additionally, the body has also directed state labs to take samples and send their report to NHRC. The NHRC has directed the Union Health Ministry, including the Drugs Controller General of India (DCGI), Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), and Directorate General of Health Services (DGHS), to investigate the supply of fake medicines in the country.

The NHRC stated in its notice, "A complaint has been received demanding action in the case of 12 children who allegedly died after consuming cough syrup in some districts of MP and Rajasthan. All concerned departments should take prompt action and respond."

The Union Health Ministry issued a health advisory on October 3, stating that cough syrups (cough and cold medicines) should not be given to children under two years of age.

The DGHS, which comes under the Ministry of Health, stated in its advisory that cough syrup should generally not be given to children under 5 years of age. If cough syrup is given to older children, it should be used cautiously.

This means that the child to whom the medicine is being given should be kept under strict supervision. The correct dosage should be given. The medicine should be given for the shortest possible time. Cough syrup should not be given with multiple other medicines. Dr Sunita Sharma of DGHS has issued this advisory.

Deaths:

11 children have died in Chhindwara, MP, after consuming the cough syrup. The first suspected case came to light on August 24. The first death occurred on September 7. After this, 6 children died one by one due to kidney failure within 15 days.

MP State Food and Drug Controller Dinesh Kumar Maurya said on Saturday, "Coldrif syrup had diethylene glycol in excess of the prescribed amount. Due to this, the syrup

was found to be poisonous." CM Mohan Yadav announced an assistance of 4-4 lakh rupees to the families of children who died after consuming Coldrif cough syrup.

Apart from MP, one death each has been reported in Bharatpur and Sikar in Rajasthan due to the consumption of another cough syrup. In the initial investigation, the name Dextromethorphan hydrobromide syrup IP came to light.

This medicine is manufactured by a private pharmaceutical company, Kessons Pharma. Here too, the reason for the children's death was stated to be kidney failure. On Saturday, the cause of death of a child in Churu is also being attributed to the consumption of cough syrup.

After this, the government took action on Saturday. The Rajasthan government has banned all 19 types of medicines from Kesen Pharma. The state's Drug Controller, Rajaram Sharma, has been suspended. Earlier, Sharma had given a clean chit to the company in the investigation.

Coldrife syrup (batch number SR-13) was seized from the unit of Srisan Pharmaceutical located in Sunguvarchatram, Kancheepuram district. Investigation revealed that non-pharmacopoeia grade propylene glycol was used in it, which was possibly contaminated with diethylene glycol (DEG) and ethylene glycol. Both chemicals are toxic substances that can damage the kidneys.

As soon as the samples were sent to the government drugs testing lab in Chennai, a report was provided within 24 hours. It was found that this batch of Coldrif syrup was toxic with 48.6% w/v DEG and 'Not of Standard Quality'. While the other four medicines (Respolite D, GL, ST and Hepsandin syrup) were found to be of Standard Quality.

Tamil Nadu Government's Action After Investigation Report

- Sale and distribution of Coldrif syrup was immediately banned across the state.
- All drug inspectors were ordered to freeze stock from wholesale and retail shops.
- Officials in Odisha and Puducherry were also alerted.
- A stop production order was issued to the company.
- A show-cause notice was also sent to cancel the manufacturing license.

The Coldrif medicine is currently banned in three states of the country, Madhya Pradesh, Kerala, and Tamil Nadu. CDSCO, the institution that controls medicines across the country, will write to the Tamil Nadu Food and Drug Administration (FDA) to take strict action against the drug company.

An investigation by officials of Tamil Nadu's Drug Department revealed that Coldrif cough syrup contains 48.6% diethylene glycol adulteration. This is a poisonous chemical.

A bench of the NHRC headed by Priyank Kanoongo took action in the matter under the Protection of Human Rights Act, 1993. He informed that the complainant has demanded the formation of a special investigation committee.

Additionally, the NHRC has made a request to investigate the production and distruibution channels of the concerned medicine. Moreover the same has also demanded that a compensation must be given to the families that have been affected by the incident.

The complainant has pointed out serious lapses in drug safety, regulations, and monitoring, and has alleged that this is a violation of children's right to life, health, and safe medicines.

Outlook

# Deaths Linked To Cough Syrup Come Under NHRC Lens; States Intensify Crackdown

https://www.outlookindia.com/healthcare-spotlight/deaths-linked-to-cough-syrup-come-under-nhrc-lens-states-intensify-crackdown

October 7, 2025

Amid reports of multiple child deaths in Madhya Pradesh and Rajasthan allegedly linked to the consumption of contaminated cough syrup, state governments and regulatory authorities have stepped up efforts to prevent further harm. The deaths have also prompted the National Human Rights Commission (NHRC) to intervene, issuing notices to state health authorities and calling for urgent investigations.

A police complaint has also been filed in the case, seeking criminal action against those responsible for the manufacture and distribution of the contaminated cough syrup.

The syrup in question — Coldrif (Batch No. SR-13), manufactured by Tamil Nadu-based Sresan Pharmaceuticals — has tested positive for diethylene glycol (DEG), a highly toxic substance known to cause acute kidney failure and death, especially in children.

The Maharashtra Food and Drug Administration (FDA) has issued a ‘Stop Use’ notice for Batch SR-13 of Coldrif syrup. In a statement, Drug Controller Dr. D.R. Gahane confirmed that the batch has not entered the retail or public supply chain in Maharashtra. The syrup was not part of any government procurement, he added.

“All available data confirms that the toxic batch is absent from the state’s healthcare and retail systems. However, we are maintaining heightened surveillance as a precaution,” the statement said.

The FDA is coordinating with Tamil Nadu’s Drug Control Administration to trace the distribution network of the contaminated batch and ensure that it does not reach Maharashtra. Drug inspectors and assistant commissioners have been directed to alert all retailers, wholesalers, and hospitals, and to immediately isolate and freeze any stock of the suspect batch if found.

Citizens in possession of the syrup are urged to report it immediately via the FDA helpline (1800 222 365), email (jchq.fda-mah@nic.in), or phone (98928 32289). The FDA has warned that DEG-contaminated medicines pose severe health risks and has advised the public to remain vigilant.

The NHRC has issued notices to the Health Departments of Madhya Pradesh and Rajasthan after reports of at least 12 child deaths, mostly in Madhya Pradesh’s Chhindwara district. A Bench led by NHRC Member Priyank Kanoongo took suo motu cognisance of the incident, calling it a potential violation of children’s right to life and health.

Initial reports from the Union Health Ministry did not detect DEG or ethylene glycol in some early samples, but multiple children reportedly suffered renal complications. The cause of death remains under investigation.

Invoking Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC has directed the affected states to collect and test syrup samples, suspend distribution, and submit an Action Taken Report within two weeks. The Commission also directed the Drugs Controller General of India (DCGI) and the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) to probe the drug’s supply chain and regulatory clearances.

Following inspection findings, the CDSCO has recommended the cancellation of Sresan Pharmaceuticals' manufacturing licence for its Kancheepuram unit. The Union Health Ministry has launched risk-based inspections at 19 pharmaceutical units across six states to identify lapses and strengthen quality control protocols.

States across India are now reviewing the presence of Coldrif’s Batch SR-13 within their supply chains. Karnataka, Telangana, and Maharashtra have all issued alerts to district-level drug officers, urging proactive checks and public awareness campaigns.

Karnataka Health Minister Dinesh Gundu Rao confirmed that the suspect batch had not been supplied in the state, but advised parents to exercise caution while administering syrups to children under five.

The Telangana government has also directed all district medical and health officers (DM&HOs) to inform the public and retailers about the contaminated batch. “If anyone is in possession of the syrup, they should report it to the local drug control authority immediately,” the advisory said.

Out of 19 samples collected from doctors and retail outlets for analysis, 10 have been tested so far. Nine were found to be within safety norms. However, Coldrif syrup was found to contain DEG above permissible limits, confirming earlier suspicions of contamination.

The ongoing probe has brought renewed attention to regulatory gaps in drug manufacturing and distribution, particularly with regard to over-the-counter pediatric medications. The tragic deaths of children have once again highlighted the need for stricter quality assurance and oversight within the pharmaceutical sector. The cough syrup linked death of the kids is also likely to cast shadow over India's reputation of being the 'pharmacy house' of the world.

The situation remains fluid, with state and central agencies actively investigating the extent of the distribution, contamination, and accountability surrounding the Coldrif batch. Public health authorities have reiterated that ensuring the safety of pediatric medications remains a top priority.

The presence of toxic substances such as diethylene glycol and ethylene glycol in Indian-manufactured cough syrups has already been linked to the deaths of at least 141 children

in The Gambia, Uzbekistan, and Cameroon since 2022, and another 12 in India in 2019—raising serious concerns over drug safety and denting the global image of India as the world’s third-largest pharmaceutical producer by volume.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

MEDICAL DIALOGUES, Online, 8.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Medical Dialogues

# Contaminated cough syrup tragedy: NHRC steps in, demands investigation

https://medicaldialogues.in/news/industry/pharma/contaminated-cough-syrup-tragedy-nhrc-steps-in-demands-investigation-156479

Written By : Ruchika Sharma Published On 2025-10-07T13:00:50+05:30 | Updated On 7 Oct 2025 1:00 PM IST

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a call to action, demanding an investigation into the alleged deaths of children linked to contaminated cough syrup. The commission has issued notices to the state governments of Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh, directing them to probe the shocking claims and immediately ban the sale of spurious medicines.

In a bold move, the NHRC has also ordered key national health authorities, including the Drugs Controller General of India (DCGI), the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), the Directorate General of Health Services (DGHS) and the Union health ministry to order an investigation into the supply of spurious drugs and instruct all regional labs in states to collect the samples of spurious drugs and submit test reports.

"The authority is also directed to order all the Chief Drugs Controllers in the concerned states to process immediately banning of the spurious drugs and submit reports," the National Human Rights Commission (NHRC) said in a notice.

The commission said it has received a complaint seeking urgent intervention in cases of the deaths of 12 children in Madhya Pradesh (Chhindwara and Vidisha districts) and some districts of Rajasthan allegedly after consuming cough syrup.

In a related development, the Tamil Nadu government recently issued a show-cause notice to Sresan Pharmaceuticals, Kancheepuram, asking why its drug manufacturing license should not be revoked entirely, following the deaths of children allegedly linked to the company's cough syrup, Coldrif.

Additionally, the Director of Public Health, Telangana, has also instructed all District Medical and Health Officers (DM&HOs) to actively sensitise the public about the alert, which was originally issued on September 4 by the Drugs Control Administration (DCA).

INDIAN WITNESS, Online, 8.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

The Indian Witness

# "Serious violation" NHRC Responds to Mounting Child Deaths from Contaminated Medicine

NHRC orders urgent probe into toxic cough syrups after 14 child deaths in three states.

https://www.indianwitness.com/news/national/serious-violation-nhrc-responds-to-mounting-child-death

By Brijesh Singh Tue, 07 Oct 2025 09:41:48 IST

In a forceful response to a mounting public health crisis, the National Human Rights Commission (NHRC) of India issued urgent notices on October 6, 2025, to the governments of Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh, mandating immediate investigations into the deaths of at least 14 children allegedly caused by contaminated cough syrups. The complaints highlight at least 12 fatalities in Madhya Pradesh's Chhindwara and Vidisha districts, with additional child deaths reported in Rajasthan districts following the consumption of Dextromethorphan Hydrobromide Syrup IP, manufactured by Kaysons Pharma in Jaipur.

The implicated product, Coldrif cough syrup produced by Sresan Pharmaceuticals in Indore, has been flagged for potential adulteration with toxic substances, though initial Union health ministry tests did not detect diethylene glycol (DEG) or ethylene glycol—known kidney toxins. The NHRC, presided over by Member Priyank Kanoongo, invoked the Protection of Human Rights Act, 1993, emphasizing that these incidents represent a profound violation of children's fundamental rights to life, health, and access to safe medicines.

The NHRC's directives extend beyond state governments to central authorities, including the Drugs Controller General of India (DCGI), Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), Directorate General of Health Services (DGHS), and the Union Health Ministry. These bodies have been ordered to launch a comprehensive probe into the supply chain of spurious drugs, instructing regional labs across the states to collect samples from pharmacies and manufacturers for rigorous testing. The commission specifically required the Chief Drugs Controllers in the affected states to expedite the banning process for the contaminated medicines and submit detailed compliance reports within weeks.

This multi-layered approach aims to trace the contamination source, dismantle illicit distribution networks, and prevent further tragedies, echoing similar scandals in 2023 where DEG-laced syrups killed over 100 children in India and Gambia. States like Karnataka have already issued alerts, halting sales of suspect brands to curb the spread.

Reports indicate the syrups were dispensed without prescriptions in rural clinics and pharmacies, exploiting lax oversight in underserved areas where affordable over-the-counter remedies are a lifeline for low-income families. The NHRC's complaint-driven

action underscores systemic failures in drug regulation, including inadequate quality checks at manufacturing units and delays in post-market surveillance, which have allowed substandard products to proliferate amid rising respiratory illnesses in the monsoon season.

In immediate fallout, the Madhya Pradesh government suspended three Food and Drugs Administration (FDA) officials—a Deputy Controller and two drug inspectors—on October 6 for negligence in monitoring the implicated batches. Several states, including Maharashtra and Bihar, have proactively banned Coldrif and similar syrups, while the CDSCO has initiated a nationwide recall and forensic analysis of Sresan Pharmaceuticals' facilities.

Health experts warn that without stringent enforcement, such lapses could recur, given India's vast pharmaceutical market, which produces 20% of the world's generic drugs but grapples with counterfeit issues. The NHRC has demanded time-bound action plans, including enhanced pharmacovigilance and public awareness campaigns to educate parents on verifying medicine authenticity via QR codes and holograms.

As investigations unfold, this crisis has ignited national outrage and calls for regulatory overhaul, with child rights activists urging the formation of a dedicated task force under the Supreme Court. The NHRC's intervention not only seeks justice for the young victims but also aims to safeguard millions of children from the perils of unregulated pharmaceuticals, potentially setting a precedent for stricter global standards in pediatric medicine safety. With test reports pending and bans rolling out, the coming weeks will test India's resolve to protect its most vulnerable from invisible poisons disguised as cures.

Udaipur Kiran

# Cough Syrup Tragedy in Madhya Pradesh: Death Toll Rises to 17, NCPCR Orders Strict Action

https://udaipurkiran.com/cough-syrup-tragedy-in-madhya-pradesh-death-toll-rises-to-17-ncpcr-orders-strict-action/

7 Oct 2025 10:02 AM by Bhupendra Singh Chundawat

Bhopal, October 7 (Udaipur Kiran): The death toll in the toxic cough syrup tragedy in Madhya Pradesh has risen to 17, with another child from Chhindwara succumbing during treatment at Nagpur Medical College on Monday. The deaths have been linked to the consumption of 'Coldrif' cough syrup, manufactured in Tamil Nadu, which contained 48.6% diethylene glycol, a highly toxic chemical.

The incident has shaken the state, prompting the formation of a Special Investigation Team (SIT), which has been sent to Tamil Nadu to probe the Shrezen Pharma factory where the syrup was produced. The Tamil Nadu government had already halted production at the facility on October 3 after the contamination was confirmed.

Chhindwara SP Ajay Pandey informed that the SIT will examine the production process, identify chemical lapses, and determine who was responsible for allowing the poisonous syrup to reach the market. He said more sections will be added to the FIR, and the number of accused may increase following the investigation.

The tragedy also exposed administrative negligence, as the first death occurred on September 4, but swift action was taken only after the death count surged. On Monday, the state government removed Drug Controller Dinesh Kumar Maurya and suspended three officials—Deputy Drug Controller Shobhit Kosta, Chhindwara Inspector Gaurav Sharma, and Jabalpur Inspector Sharad Kumar Jain—for delayed action in banning the syrup and testing samples.

The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) and the National Human Rights Commission (NHRC) have taken serious cognizance of the incident. The NHRC issued notices to the governments of Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh, directing immediate investigations and a nationwide crackdown on spurious and unsafe drugs. The Union Health Ministry, DCGI, and CDSCO have been instructed to collect samples and submit lab reports from across the country.

NCPCR member Priyank Kanoongo said, "This is a grave national concern. All states have been instructed to immediately ban the sale of the suspected cough syrup and send test reports. Those found guilty—whether officials or manufacturers—will face strict action."

Following the tragedy, Haryana, Jharkhand, Maharashtra, and Karnataka have banned Coldrif, while Jharkhand has also restricted Respifresh and Relif brands.

Chief Minister Dr. Mohan Yadav, after visiting affected families in Parasia, said, “This is not just your grief; it is the grief of the entire state. The government will ensure that no culprit is spared.” He announced immediate administrative action and reaffirmed that preventing such tragedies is now the top priority.

Authorities noted that the DCGI and CDSCO had earlier restricted the use of chlorpheniramine maleate and phenylephrine HCl combinations in children below four years, and required mandatory warning labels—rules allegedly violated by Shrezen Pharma. The investigation aims to ensure accountability and justice for the victims.

Statesman

# Congress demands judicial probe into cough syrup deaths, compensation for families

https://www.thestatesman.com/india/congress-demands-judicial-probe-into-cough-syrup-deaths-compensation-for-families-1503496105.html/amp

Statesman News Service | October 7, 2025 6:02 pm

The Congress on Tuesday demanded a judicial probe into the deaths of several children in different states, allegedly caused by the consumption of a contaminated cough syrup. The party also urged the governments of Madhya Pradesh and Rajasthan to provide adequate compensation to the affected families.

Addressing a press conference at the AICC headquarters, Leaders of Opposition Tika Ram Jully and Umang Singhar said there was gross negligence on the part of the authorities in allowing the sale of the cough syrup despite reports of related deaths in the past. “The company supplying the cough syrup had been blacklisted earlier, and despite that, it was allowed to supply the syrup,” they said. The syrup was found to contain a highly toxic chemical, diethylene glycol (DEG), known to cause kidney damage in children.

Singhar and Jully pointed out that the main reason for such gross negligence was the systematic failure of administration in the two states, where both Chief Ministers have to “look towards Delhi” for every step they take and every move they make. They demanded a thorough investigation to identify all the culprits involved in this massive scandal.

The Congress leaders emphasised that most of the families whose children died came from economically poor backgrounds and have suffered a double blow of losing their kids and incurring huge debts due to treatment expenses. “These families must be adequately compensated to help them come out of the debt,” they said.

Seeking a judicial probe, the Congress leaders pointed out that such a tragedy involving the death of about 20 kids could have been avoided if the authorities had taken timely action. The National Human Rights Commission (NHRC) has also taken cognizance of the matter and issued notices to the Health Departments of Madhya Pradesh and Rajasthan.

The government has taken steps to address the issue, including risk-based inspections at 19 pharmaceutical manufacturing units across six states. The Health Ministry has also advised states to step up disease surveillance and reporting.

Mahamedia

## Cough Syrup deaths: Plea in SC seeks CBI probe

https://mahamedianews.com/en/india-news/news/cough-syrup-deaths--plea-in-sc-seeks-cbi-probe

2025-10-07 18

NEW DELHI [Maha Media]: A plea has been moved in the Supreme Court seeking an inquiry and systemic reform in drug safety mechanisms against the backdrop of deaths of children in Madhya Pradesh and Rajasthan, allegedly due to the consumption of toxic cough syrups.

Filed by advocate Vishal Tiwari, the plea sought a court-monitored probe into the incidents and also a direction for the constitution of a National Judicial Commission or Expert Committee headed by a retired Supreme Court judge.

The plea contended that a probe under the supervision of a retired Supreme Court judge would ensure fairness and uniformity. The petition submitted that separate probes at the state level have led to fragmented accountability, which has led to repeated lapses that allow hazardous formulations to reach the market.

It also urged the apex court that all pending FIRs and investigations concerning the deaths of children caused by toxic cough syrups across states should be transferred to the CBI. The plea sought the court's direction to the Centre to constitute a national-level judicial or expert body to identify the regulatory failures that allowed substandard medicines to reach the market.

The plea has also sought a direction from the court to mandate toxicological testing of all suspect products through NABL-accredited laboratories before any further sale or export is permitted. The petition has been filed amid reports from Madhya Pradesh and Rajasthan, where several children allegedly died after consuming a particular kind of cough syrup.

Meanwhile, the National Human Rights Commission on Monday issued notices to the Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh governments, directing them to probe allegations of children's deaths due to contaminated cough syrup and immediately ban the sale of spurious medicines.

It has also directed the Union Health Ministry, the Drugs Controller General of India (DCGI), the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), and the Directorate General of Health Services (DGHS) to order an investigation into the supply of spurious drugs and instruct all regional labs in states to collect the samples of spurious drugs and submit test reports.

Zoom News

## Supreme Court: Case of children dying after consuming cough syrup reaches SC- demand for seizure of all stock

https://www.zoomnews.in/amp/en/news-detail/case-of-children-dying-after-consuming-cough-syrup-reaches-sc-demand-for-seizure-of-all-stock.html

Vikrant Singh Shekhawat | Updated on: 07-Oct-2025 01:13 PM IST

Supreme Court: The case of children dying from consuming 'Coldrif' cough syrup in Madhya Pradesh and Rajasthan has now reached the Supreme Court. Lawyer Vishal Tiwari has filed a public interest litigation in the Supreme Court regarding this serious matter, demanding a CBI investigation and the seizure of the cough syrup's stock.

18 Children Die Due to Toxic Cough Syrup

According to official data, 18 children have died so far in Madhya Pradesh and Rajasthan after consuming 'Coldrif' cough syrup. Sixteen of these deaths were reported in Chhindwara district of Madhya Pradesh and two in Bharatpur and Sikar in Rajasthan. Investigations revealed that the syrup contained 48.6% diethylene glycol (DEG), a toxic chemical that causes kidney failure. This chemical has proven fatal for children, and the deaths continue unabated.

What is the demand in the public interest litigation?

The following are the key demands in the PIL filed by lawyer Vishal Tiwari:

CBI investigation: All relevant FIRs should be investigated by the Central Bureau of Investigation (CBI).

Supervision by a retired Supreme Court judge: The investigation into the manufacturing, regulation, testing, and distribution of cough syrups should be conducted under the supervision of a retired Supreme Court judge.

National Investigation Committee: A thorough investigation into this matter should be conducted by the National Judicial Commission or an expert committee.

Seizure of syrup stocks: All existing stocks of the banned 'Coldrif' cough syrup should be immediately seized.

What action has been taken so far?

The central and state governments have taken some steps in this matter:

Central government action: Risk-based inspections have been initiated at 19 drug manufacturing units in six states.

National Human Rights Commission (NHRC): Notices have been issued to the governments of Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh, directing them to conduct an immediate investigation and ban counterfeit drugs.

State Governments Responsible: Local authorities in Madhya Pradesh and Rajasthan have begun testing syrup samples, but no concrete results have yet been released.

Why are children's lives at risk?

The high levels of diethylene glycol (DEG) found in 'Coldrif' cough syrup have proven fatal for children. This chemical, when ingested, causes severe kidney damage, leading to kidney failure and death. Experts say that negligence in drug manufacturing and a lack of quality control are the main causes of this tragedy.

Lalluram

# कफ सिरप कांड: SIT आज पहुंचेगी तमिलनाडु, दवा कंपनी पर शिकंजा; नागपुर में बच्चों के इलाज के बारे में रिपोर्ट लेगी टीम, NHRC ने लिया संज्ञान

https://lalluram.com/chhindwara-cough-syrup-scandal-sit-to-reach-tamil-nadu-today-tightens-noose-on-pharmaceutical-company/

Rituraj Vaishnav | 07 Oct 2025, 01:27 PM

मध्यप्रदेश

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' से 16 मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं मामले को लेकर गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) आज तमिलनाडु पहुंच रही है। 12 सदस्यीय इस टीम का मकसद है दवा बनाने वाली कंपनी के राज उजागर करना। कंपनी की फैक्ट्री कांचीपुरम में स्थित है, जहां से सिरप की सप्लाई हुई थी। SIT वहां कंपनी से जुड़े लोगों से सख्त पूछताछ करेगी। फैक्ट्री का दौरा कर सबूत जुटाएगी।

नागपुर में बच्चों के इलाज का रिपोर्ट लेगी टीम

सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के बाद कुछ और आरोपी बनाए जा सकते हैं। अभी तक डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर निलंबित किया जा चुका है, जिन्होंने ज्यादातर बच्चों को यह सिरप लिखा था। कंपनी के खिलाफ भी FIR दर्ज है, और जांच में सिरप में 48% से ज्यादा जहरीला केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है। दूसरी तरफ, स्वास्थ्य विभाग की टीम नागपुर पहुंच चुकी है। यहां 14 बीमार बच्चों में से 6 ICU में हैं। टीम इलाज की रिपोर्ट लेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी।

NHRC ने लिया संज्ञान

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने सिरप की बिक्री पर पूर्ण बैन लगा दिया है, और प्रभावित परिवारों को 4 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने भी संज्ञान ले लिया है। आयोग ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि दोषियों को सजा सुनिश्चित हो।

AGNIBAN, Online, 8.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Agniban

# MP में कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत, एनएचआरसी ने उठाए सख्त कदम

https://www.agniban.com/children-died-cough-syrup-mp-nhrc-takes-strict-action/

October 07, 2025 | AGNIBAN

भोपाल । तमिलनाडु में बने कफ सिरप की खेप ने मध्य प्रदेश में कहर बरपा रखा है। सोमवार को छिंदवाड़ा की एक और मासूम बच्ची की मौत के बाद मरने वाले बच्चों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। ताजा प्रकरण में छिंदवाड़ा के तामिया जूनापानी निवासी नवीन डेहरिया की डेढ़ साल की बेटी जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज नागपुर में चल रहा था ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है।

उल्लेखनीय है कि कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' के सेवन से बच्चों की किडनी फेल होने के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। अब इस घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) तमिलनाडु रवाना हो चुकी है।। कोल्ड्रिफ सिरप के सैंपल में डायथिलीन ग्लायकॉल की मात्रा 48.6 प्रतिशत पाई गई, जो बेहद खतरनाक और मानव शरीर के लिए घातक रसायन है। इसी के बाद तमिलनाडु सरकार ने तीन अक्टूबर को श्रेसन फार्मा कंपनी में उत्पादन पर तत्काल रोक लगा दी। अब मध्य प्रदेश पुलिस इस फैक्टरी की जांच करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उत्पादन में कौन-सी गंभीर गड़बड़ी हुई और किन परिस्थितियों में यह जहरीला सिरप बाजार में पहुंचा।

छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बताया कि एसआईटी मंगलवार को फैक्टरी पहुंचकर जांच करेगी और सिरप के निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक तत्वों की पूरी पड़ताल करेगी। जांच दल यह भी देखेगा कि उत्पादन प्रक्रिया में लापरवाही कैसे हुई और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही। उनके अनुसार, जांच के बाद एफआईआर में और धाराएं जोड़ी जाएंगी तथा आरोपित व्यक्तियों की संख्या बढ़ सकती है।

दरअसल, जहरीले कफ सिरप से हुई इन मौतों के पीछे प्रशासनिक सुस्ती भी उजागर हुई है। पहली मौत 4 सितंबर को दर्ज हुई थी, लेकिन जब मौतों का आंकड़ा दो अंकों में पहुंच गया और मामले ने मीडिया के जरिए तूल पकड़ा, तब जाकर प्रशासन ने कार्रवाई की। सोमवार को राज्य सरकार ने ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य को उनके पद से हटा दिया, जबकि डिप्टी ड्रग कंट्रोलर शोभित कोष्टा, छिंदवाड़ा के औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा और जबलपुर के औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन को निलंबित कर दिया गया। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाने में देरी की, पर्याप्त सैंपलिंग नहीं की और जो सैंपल लिए गए उनकी जांच रिपोर्ट आने में भी अनावश्यक देरी की। यही लापरवाही मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ी।

इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी इस पूरे मामले पर गंभीर संज्ञान लिया है। सोमवार को आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर बच्चों की मौतों की जांच करने और नकली या संदिग्ध दवाओं की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, औषधि नियंत्रक जनरल और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को भी सख्त आदेश दिया है कि वे देशभर में नकली दवाओं की आपूर्ति की गहन जांच करें। इसके साथ ही सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को संदिग्ध दवाओं के नमूने एकत्र कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा, "देश भर में कई स्थानों पर कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की अत्यंत गंभीर घटना का संज्ञान ले कर सभी संबंधित राज्य सरकारों को संदिग्ध कफ सिरप की बिक्री तत्काल रोकने के निर्देश देते हुए जांच रिपोर्ट आहूत की है।राज्य सरकार व केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसियों को उपरोक्त कफ सिरप की सैंपल टेस्टिंग कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए हैं।इस मामले में लिप्त अथवा लापरवाह अफसरों एवं दवा कंपनी तथा अन्य लोगों से पूरी सख्ती से निपटा जाएगा।"

घटना के बाद हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने भी कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। झारखंड सरकार ने तो इससे भी आगे बढ़ते हुए रेस्पीफ्रेश और रिलिफ कफ सिरप जैसे अन्य ब्रांड्स की बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी है।

इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर सोमवार को खुद परासिया पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह दुख केवल प्रभावित परिवारों का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाते हुए कहा, "यह आपकी नहीं, मेरी और हम सबकी पीड़ा है। आपके बच्चों का दुख मेरा भी है। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।" उन्होंने कहा कि इस घटना ने सरकार को गहराई से झकझोर दिया है और अब प्रदेश में इस तरह की त्रासदियों की पुनरावृत्ति रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री ने मौके पर ही कई सख्त फैसले लिए और जिम्मेदारों को तत्काल उसके पद से हटाने के आदेश दिए।

गौरतलब है कि भारत सरकार के डीसीजीआई और सीडीएससीओ द्वारा पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि क्लोरफेनिरामिन मेलिएट और फिनाइलएफ्रिन एचसीआई का संयोजन चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही दवा के लेबल पर यह चेतावनी लिखना अनिवार्य है। लेकिन श्रेसन फार्मा ने इन नियमों की खुलेआम अवहेलना की। इसी कारण राज्य शासन ने कंपनी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। वहीं, अब सबकी निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी हैं, ताकि मासूमों की मौत का यह सिलसिला थमे और दोषियों को कठोरतम सजा मिले।

IND24

# राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक्शन: MP समेत तीन राज्यों और DCGI को जारी किया नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही, भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) सहित कई केंद्रीय एजेंसियों को भी जांच के निर्देश दिए हैं।

https://ind24.tv/news/NHRC_Action

Sanjay Purohit | Created AT: 6 hours ago

कफ सिरप से कथित रूप से बच्चों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही, भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) सहित कई केंद्रीय एजेंसियों को भी जांच के निर्देश दिए हैं। NHRC ने इन राज्यों में कथित रूप से दूषित और नकली कफ सिरप के सेवन से बच्चों की जान जाने की खबरों का संज्ञान लेते हुए संबंधित राज्यों से तथ्यात्मक रिपोर्ट और तत्काल कार्रवाई की जानकारी मांगी है।

नकली दवाओं पर तत्काल रोक के निर्देश

आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिए हैं कि वे नकली दवाओं की बिक्री पर तुरंत रोक लगाएं और संबंधित रिपोर्ट सौंपें। साथ ही, CDSCO, DGHS और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नकली दवाओं की आपूर्ति पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उनकी जांच के लिए नमूने एकत्र कर जल्द रिपोर्ट दी जाए।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

JANTA SE RISHTA, Online, 8.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Janta Se Rishta

# मध्य प्रदेश-राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला: एनएचआरसी ने दिए जांच के आदेश

https://jantaserishta.com/others/nhrc-orders-probe-into-deaths-of-children-due-to-cough-syrup-in-madhya-pradesh-and-rajasthan-4306824

7 अक्तूबर 2025

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोमवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्वास्थ्य विभागों के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया। यह नोटिस दोनों राज्यों में कथित तौर पर नकली कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत के मामले में जारी किया गया है।

एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक शिकायत पर ध्यान दिया, जिसमें दवा सुरक्षा और नियामक तंत्र में गंभीर खामियों का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण यह त्रासदी हुई।

शिकायत में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और विदिशा जिलों के साथ-साथ राजस्थान के कुछ जिलों में हुई घटनाओं में शीर्ष मानवाधिकार निकाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है, जहां कथित तौर पर खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत हो गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुरुआती परीक्षणों में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले पदार्थ नहीं मिले, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बच्चों की मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

कई मामलों में किडनी फेल होने और अन्य जटिलताओं की बात सामने आई है। शिकायतकर्ता ने इसे बच्चों के बुनियादी अधिकारों, जैसे जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षित दवाओं के अधिकार का उल्लंघन बताया है।

शिकायत में कफ सिरप के निर्माण, वितरण, नियामक खामियों और संभावित मिलावट की विशेष जांच की मांग की गई है।

एनएचआरसी ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया है। उन्हें तुरंत जांच करने, कफ सिरप के नमूने एकत्र करने, क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में उनकी जांच कराने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (डीसीजीआई), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नकली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही, संबंधित राज्यों के सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को नमूने एकत्र करने और उनकी जांच करने का आदेश दिया गया है।

एनएचआरसी ने कहा, "सभी संबंधित राज्यों के मुख्य ड्रग्स कंट्रोलरों को नकली दवाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाता है।"

JANTA SE RISHTA, Online, 8.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

सभी अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर एनएचआरसी को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने के लिए कहा गया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

NDTV MP Chattisgarh

## Cough Syrup Death: कफ सिरप से 12 बच्चों की मौत मामले पर NHRC सख्त, जांच के दिए आदेश

NHRC Orders Probe: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और विदिशा जिलों के साथ-साथ राजस्थान के कुछ जिलों में हुई घटनाओं को लेकर दर्ज एक शिकायत में शीर्ष मानवाधिकार निकाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है, जहां कथित तौर पर खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत हो चुकी है.

https://mpcg.ndtv.in/madhya-pradesh-news/nhrc-orders-probe-deaths-of-children-cough-syrup-death-madhya-pradesh-and-rajasthan-nhrc-takes-action-cough-syrup-death-investigation-mp-news-9408649/amp/1

Written by:शिव ओम गुप्ता

(with inputs from IANS)

मध्य प्रदेश न्यूज़

अक्टूबर 07, 2025 07:36 am IST

Read Time:4 mins

NHRC In Action: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कप सिरप से हुई बच्चों की मौत के लेकर दोनों राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया है. NHRC ने यह नोटिस दोनों राज्यों में कथित तौर पर नकली कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत के मामले में जारी किया है.

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और विदिशा जिलों के साथ-साथ राजस्थान के कुछ जिलों में हुई घटनाओं को लेकर दर्ज एक शिकायत में शीर्ष मानवाधिकार निकाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है, जहां कथित तौर पर खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत हो चुकी है.

नकली कप सिरप पीने से बच्चों की मौत को लेकर दर्ज कराई गई थी शिकायत

गौरतलब है मध्य प्रदेश और राजस्थान में नकली कप सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत को लेकर एनएचआरसी में एक शिकायत कराई गई थी. एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच को भेजी गई शिकायत में दवा सुरक्षा और नियामक तंत्र में गंभीर खामियों को लेकर आरोप लगाया गया था.

कप सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे पदार्थ नहीं मिले

रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुरुआती परीक्षणों में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले पदार्थ नहीं मिले, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बच्चों की मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है. हालांकि कई मामलों में किडनी फेल होने और अन्य जटिलताओं की बात सामने आई है.

एनएचआरसी में दर्ज शिकायत में शिकायतकर्ता ने इसे बच्चों के बुनियादी अधिकारों, जैसे जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षित दवाओं के अधिकार का उल्लंघन बताया है. शिकायत में कफ सिरप के निर्माण, वितरण, नियामक खामियों और संभावित मिलावट की विशेष जांच की मांग की गई है.

एमपी, राजस्थान व यूपी की सरकारों के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिवों को नोटिस

एनएचआरसी ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत कार्रवाई करते हुए एमपी, राजस्थान और यूपी की सरकारों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों को नोटिस कर उन्हें तुरंत जांच करने, कफ सिरप के नमूने एकत्र करने, क्षेत्रीय लैब में जांच कराने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल रोक निर्देश दिए हैं.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नकली दवाओं की सप्लाई चेन की गहन जांच के निर्देश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (डीसीजीआई), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नकली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला की गहन जांच करने का निर्देश दिया है. साथ ही, संबंधित राज्यों के सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को नमूने एकत्र करने और उनकी जांच करने का आदेश दिया गया है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी संबंधित राज्यों के मुख्य ड्रग्स कंट्रोलरों को नकली दवाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है और अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने के लिए कहा है.

दो सप्ताह के भीतर अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने के लिए कहा

एनएचआरसी ने जारी नोटिस में कहा, "सभी संबंधित राज्यों के मुख्य ड्रग्स कंट्रोलरों को नकली दवाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाता है. सभी अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर एनएचआरसी को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने के लिए कहा गया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.

Bharat Express

# मध्य प्रदेश-राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर एनएचआरसी ने दिए जांच के आदेश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्वास्थ्य विभागों के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया. यह नोटिस दोनों राज्यों में कथित तौर पर नकली कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत के मामले में जारी किया गया है.

https://bharatexpress.com/india/nhrc-orders-probe-into-deaths-of-children-due-to-cough-syrup-mp-rajasthan-575753

Bharat Express Desk October 7, 2025 8:53 am

Edited by Vaibhav Gupta

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोमवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्वास्थ्य विभागों के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया. यह नोटिस दोनों राज्यों में कथित तौर पर नकली कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत के मामले में जारी किया गया है. एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक शिकायत पर ध्यान दिया, जिसमें दवा सुरक्षा और नियामक तंत्र में गंभीर खामियों का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण यह त्रासदी हुई.

क्या था मौत का कारण?

शिकायत में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और विदिशा जिलों के साथ-साथ राजस्थान के कुछ जिलों में हुई घटनाओं में शीर्ष मानवाधिकार निकाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है, जहां कथित तौर पर खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत हो गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुरुआती परीक्षणों में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले पदार्थ नहीं मिले, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बच्चों की मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है.

कई मामलों में किडनी फेल होने और अन्य जटिलताओं की बात सामने आई है. शिकायतकर्ता ने इसे बच्चों के बुनियादी अधिकारों, जैसे जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षित दवाओं के अधिकार का उल्लंघन बताया है. शिकायत में कफ सिरप के निर्माण, वितरण, नियामक खामियों और संभावित मिलावट की विशेष जांच की मांग की गई है.

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग को नोटिस

एनएचआरसी ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया है. उन्हें तुरंत जांच करने, कफ सिरप के नमूने एकत्र करने, क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में उनकी जांच कराने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया गया है.

दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (डीसीजीआई), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को नकली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला की गहन

जांच करने का निर्देश दिया है. साथ ही, संबंधित राज्यों के सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को नमूने एकत्र करने और उनकी जांच करने का आदेश दिया गया है.

एनएचआरसी ने कहा, “सभी संबंधित राज्यों के मुख्य ड्रग्स कंट्रोलरों को नकली दवाओं पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाता है.” सभी अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर एनएचआरसी को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने के लिए कहा गया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.

NavShakti

# कफ सिरपमुळे मृत्यू : मानवी हक्क आयोगाची नोटीस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सोमवारी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी केली आहे. कफ सिरपमुळे मुलांच्या मृत्यूच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आणि बनावट औषधांची विक्री तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

https://marathi.freepressjournal.in/nation/nhrc-issues-notice-to-mp-rajasthan-up-over-cough-syrup-deaths

Swapnil S | Published on: 07 Oct 2025, 10:06 am

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सोमवारी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी केली आहे. कफ सिरपमुळे मुलांच्या मृत्यूच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आणि बनावट औषधांची विक्री तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, औषध नियंत्रक महासंचालक, सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन आणि आरोग्य सेवा महासंचालक यांना बनावट औषध पुरवठ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच सर्व राज्यातील प्रादेशिक प्रयोगशाळांना बनावट औषधांचे नमुने गोळा करून चाचणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित राज्यातील सर्व मुख्य औषध नियंत्रकांना बनावट औषधांवर ताबडतोब बंदी घालण्याचे आदेश देणे व अहवाल सादर करणे हे प्राधिकरणाने आदेशित केले आहेत, असे आयोगाने नोटिसीत म्हटले आहे. आयोगाला मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील काही जिल्ह्यांमध्ये १२ मुलांच्या मृत्यूप्रकरणी तातडीच्या हस्तक्षेपाची तक्रार प्राप्त झाली आहे.

आयोगाच्या सदस्य प्रियंक कनुगो यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचने १९९३ च्या मानवाधिकार संरक्षण कायद्याचा विचार केला आहे.

नोटीसमध्ये म्हटले की, 'राजस्थान, जयपूर येथील आरोग्य व कौटुंबिक कल्याण विभागाचे मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश, भोपाल येथील आरोग्य व कौटुंबिक कल्याण विभागाचे मुख्य सचिव आणि उत्तर प्रदेश, लखनऊ येथील आरोग्य व कौटुंबिक कल्याण विभागाचे मुख्य सचिव यांना नोटीस जारी करून तक्रारीत केलेले आरोप तपासण्याचे, कफ सिरपाचे नमुने प्रादेशिक लॅबमध्ये तपासणीसाठी गोळा करणे व बनावट औषधांची तत्काळ विक्री बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ABP Live

# Coldriff सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत, MP-UP से लेकर तमिलनाडु तक लगा बैन, SC पहुंचा मामला I बड़े अपडेट

Cough Syrup Death Case: एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर उन्हें दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया.

https://www.abplive.com/news/india/coldriph-cough-syrup-death-in-india-chhindwara-rajasthan-up-mp-tamil-nadu-punjab-govt-action-3025072

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 07 Oct 2025 10:22 PM (IST)

Source : ANI

भारत में कफ सिरप पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद कई राज्यों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने की बात कही.

एनएचआरसी ने इन राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर उन्हें दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के आरोपों की जांच करने और नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है. याचिकाकर्ता ने दवाओं के निर्माण, परीक्षण और वितरण की व्यवस्था की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की है. बच्चों की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग याचिका में की गई है.

महाराष्ट्र सरकार ने जारी की चेतावनी

महाराष्ट्र एफडीए ने एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है कि रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ कफ सिरप में सुरक्षित सीमा से अधिक विषाक्त डायएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) मौजूद है. बिक्री, वितरण या उपयोग पर रोक है और लाइसेंसधारियों को किसी भी स्टॉक की तुरंत सूचना देनी होगी.

इसे लेकर तमिलनाडु सरकार ने 44 पेज की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी श्रीसेन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर काचीपुरम में 39 गंभीर और 325 बड़ी खामियां निकली.

कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी पर तमिलनाडु में बड़ा खुलासा

रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी किसी भी स्तर पर GMP (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज) के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही थी. कंपनी फार्मास्यूटिकल ग्रेड के बजाय गैर-फार्मास्यूटिकल ग्रेड प्रोपलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल कफ सिरप निर्माण में कर रही थी.यह केमिकल बिना इनवॉइस अलग-अलग तिथियों पर 50-50 किलो के पैक में खरीदा गया. भुगतान नकद या गूगल-पे के माध्यम से किया गया था.

तमिलनाडु सरकार ने फैक्ट्री का लाइसेंस सस्पेंड किया

खरीदे गए प्रोपलीन ग्लाइकोल में डायथिलीन ग्लाइकोल 48.6 परसेंट और एथिलीन ग्लाइकोल पाए गए जो बेहद विषैले तत्व हैं और इंसानी शरीर के लिए जानलेवा साबित होते हैं. दवाइयों को गंदगी, कीचड़ और कीड़ों से भरे माहौल में बनाया और संग्रहित किया जा रहा था यहां ड्रेन सिस्टम नहीं था, जिससे चूहे, कीड़े-मकौड़े अंदर घुस रहे थे. तमिलनाडु सरकार ने फैक्ट्री का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है

पंजाब में कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन

पंजाब में भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप को बैन कर दिया गया है. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब ने मध्य प्रदेश में हुई मौतों को देखते फैसला लिया है. छिंदवाड़ा में कफ सिरप मामले में आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को 9 अगस्त तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है. मध्य प्रदेश में कफ सिरफ से 21 मौतें हुई हैं, जिसमें से छिंदवाड़ा में 18, बैतूल में 2, पंढुरना में 1 बच्चे की मौत हुई. राजस्थान में भी कफ सिरफ से तीन मौतें हुई है.

केरल में भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन

केरल में भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन कर दिया गया है. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने मंगलवार (7 अक्टूबर 2025) को कहा कि कफ सिरप के प्रबंधन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति की गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि निजी अस्पतालों और दवा दुकानों में इस कफ सिरप की बिक्री न हो. उन्होंने आगे कहा, "हमने एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में पहले ही ऐसा कर लिया है और राज्य में इनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन कर दिया गया है. यूपी में कई जगहों पर कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री रोकने के लिए छापेमारी भी की जा रही है. यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, "यह बहुत दुखद है कि कई बच्चों ने कफ सिरप का सेवन करने के बाद अपनी जान गंवा दी है. हमारी सरकार ने कभी भी ऐसा कफ सिरप नहीं खरीदा."

Clarion India

# Muslim Teenager in UP's Muzaffarnagar Loses Vision After Alleged Police Beating

https://clarionindia.net/muslim-teenager-in-ups-muzaffarnagar-loses-vision-after-alleged-police-beating/

Team Clarion | Date: October 7, 2025

Medical reports from a local health centre note that the boy had lost vision in one eye. He has now been referred to a hospital in Meerut for surgery

NEW DELHI — A 13-year-old Muslim boy in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, has lost vision in his left eye allegedly after being beaten by police while in custody. The incident last week has sparked outrage, with the boy's family filing complaints with the National Human Rights Commission (NHRC), the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), and district authorities.

According to the boy's father, the family owns a chicken shop that had been closed for close to two weeks because of the Hindu festivities of Navratri. The shop reopened on September 27, and the boy announced the reopening and prices at the nearby mosque. The boy informed the public that chicken was available at ₹140 per kg due to low demand because of the Navratri festivities. However, someone complained about the announcement, and the police arrived, taking the boy into custody, media reports reaching here said on Monday.

The boy's family alleges that the police assaulted and intimidated him while in custody, resulting in serious injuries that led to the loss of vision in one eye. The family claims that CCTV footage shows the boy being taken away by the police. The family has sought action against the police personnel involved.

The father said that when he reached the police outpost, his son was behind bars with both feet tied. "Police told us it was a small issue and asked us to return after noon. When I returned, they said I had been fined under Section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS). My son had bruises all over his body and said he could no longer see properly," the father was quoted as saying.

He also claimed that the police accused him of possessing a country-made pistol after finding a photo of one on his son's phone. "It was just a picture saved from the Internet. My son later said police beat and videographed him until he admitted the weapon belonged to me," the father said.

Medical reports from a local health centre noted that the boy had lost vision in one eye due to "trauma caused an hour ago." He has now been referred to a hospital in Meerut for surgery.

In his written complaint, the father alleged: “My son was abducted, beaten severely at the Biralsi police outpost, and now has a serious eye injury. The inspector is threatening to jail me if I pursue the case.”

Responding to queries from media personnel, Muzaffarnagar Superintendent of Police Sanjai Kumar acknowledged that the matter has been reported to them. “Our initial inquiry suggests that the boy had a pre-existing eye condition and was receiving treatment for the past four years. The matter is being investigated,” he said.

There have been previous incidents of alleged police misconduct in Muzaffarnagar. For instance, a controversy arose when the police asked food sellers on the Kanwar Yatra route to display the names of their owners and employees, sparking accusations of discrimination against Muslims. The police clarified that the move was aimed at avoiding confusion among Kanwariyas and maintaining law and order.

Siyasat

## UP teenager blinded in one eye after police brutality over mosque announcement

The victim's father owns a chicken shop which had been closed for the past ten days. Upon its reopening, his son went to the mosque to announce that the chicken would be sold at a lower price.

https://www.siasat.com/up-teenager-blinded-in-one-eye-after-police-brutality-over-mosque-announcement-3280983/amp/

This post was last modified on October 7, 2025 8:34 pm

A 13-year-old Muslim boy in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, lost vision in his left eye due to alleged police brutality while in detention after his announcement at a local mosque "hurt local sentiments".

The family lodged complaints with the district authorities, National Human Rights Commission (NHRC), and the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), accusing the involved police officers of assault and intimidation, as he was threatened with police action if he complained.

The victim's father owns a chicken shop which had been closed for the past ten days. Upon its reopening, his son went to the mosque to announce that the chicken would be sold at a lower price.

"My son went to the mosque near our shop and announced that our shop has reopened and that chicken would now be available at prices that are cheaper than usual at Rs 140 per kg due to lesser demand during Navratri," the victim's father was quoted by The Indian Express.

Also Read

The announcement received complaints, acting on which, a police van patrolling the village picked the teen from the streets.

"We were informed (of the incident) by neighbours who saw him being taken away," his father claimed.

The boy is reportedly seen being taken away by the police in a nearby CCTV footage.

The father stated that upon arriving at the police outpost, he found his son behind bars with both feet bound.

"Police told us it was a small issue and asked us to return in the afternoon. When I came back, they said I had been fined under Section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS). My son had bruises all over his body and said he could no longer see properly," he alleged.

Section 173 of BNSS deals with the mandatory recording of information about serious crimes. The police claimed to have fined him to maintain peace in the area.

Moreover, the father also claimed that the police charged him with owning a country-made pistol, a picture of which was found in the boy’s phone.

“It was just a picture he had saved from the Internet. We don’t own any pistols. But I was fined for possessing one,” he stated.

His son reportedly accepted the accusation after being pressured during a police questioning session that was videotaped.

“Later, my son said he had been beaten and videographed until he agreed to their version,” the father said.

His family took him to a local health centre where medical reports indicated the boy had lost sight in one eye because of “trauma caused an hour ago”. He has since been transferred to a hospital in Meerut for specialised surgery.

Meanwhile, Muzaffarnagar police have stated X, clarifying that the victim had been suffering an eye injury for the past five years and that he was “safely” returned back home.

“The boy who made the announcement was called for a discussion with his family members, and after the discussion, he was safely handed over to the family members who accompanied him. The boy has been receiving treatment for his eye for the past five years. The allegations of assault and other charges made against the police are completely false and baseless,” the statement read.

The Kashmiriyat

## U.P: 13-year-old loses eyesight after alleged custodial torture, family approaches NHRC

https://thekashmiriyat.co.uk/u-p-13-year-old-loses-eyesight-after-alleged-custodial-torture-family-approaches-nhrc/

October 7, 2025 by News Desk

A disturbing case of alleged custodial torture has emerged from Muzaffarnagar, where a 13-year-old boy reportedly lost vision in one eye after being allegedly beaten while in police custody.

The boy's father, Showkat Ahmad, said the incident occurred after his son made an announcement at a local mosque about the reopening of their chicken shop, which had been closed for two weeks. "He went to the mosque and told people that chicken would be sold at ₹140 per kg. Someone complained, and he was picked up by police," he said. Neighbours later informed the family about the boy being taken away, a claim supported by nearby CCTV footage.

"When I went to the police station, my son was behind bars with his feet tied. The police told me it was a small matter and asked us to return later," the father said. "But when we came back, he had injuries all over his body and complained that he couldn't see properly."

Police initially claimed that the boy possessed a country-made pistol, which the family denied. "It was just a picture saved on his phone. My son told me that the police beat him, videographed him, and forced him to admit ownership," the father added.

Medical reports confirmed that the boy lost vision in one eye due to trauma sustained during custody. The family has registered complaints with the National Human Rights Commission (NHRC), the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), and local authorities. Showkat Ahmad further alleged, "The inspector has been threatening me for filing the case."

Muzaffarnagar Superintendent of Police, Sanjai Kumar, said, "The boy's announcement hurt the sentiments of some locals. Our preliminary investigation suggests he had a pre-existing eye condition and was under treatment for the past four years. The investigation is underway to find out more."

A local SHO also said a fine was imposed on the boy's father "to maintain law and order," but emphasized that a detailed investigation is ongoing.

Human rights observers have expressed concern over the alleged misconduct and called for accountability, warning that such incidents undermine public trust in law enforcement and endanger children.

The Hans India

## NHRC seeks answers from MP govt in incidents of child branding, electrocution deaths

https://www.thehansindia.com/amp/news/national/nhrc-seeks-answers-from-mp-govt-in-incidents-of-child-branding-electrocution-deaths-1012550

The Hans India | Update: 2025-10-07 12:39 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of two separate incidents in Madhya Pradesh that raise grave concerns over the safety and dignity of children.

The Commission has issued notices to senior district officials, demanding detailed reports within two weeks.

The first incident, reported from Jhabua district, involves three children suffering from pneumonia who were allegedly branded with a hot iron rod by a local faith healer. Shockingly, the parents themselves had taken the children to the healer, believing in traditional practices over medical treatment.

Doctors later confirmed that the children were indeed suffering from pneumonia and bore visible burn marks on their bodies. One of the children is said to be in critical condition.

The NHRC, in its preliminary observation, stated that if the contents of the media report are accurate, they point to a serious violation of human rights. “Notices have been sent to the District Magistrate and the Superintendent of Police, Jhabua, seeking a comprehensive report on the incident, including the action taken against the faith healer and the steps being initiated to prevent such practices in the future,” a NHRC statement said.

In a separate tragedy, two children aged 8 and 10 lost their lives due to electrocution while playing inside a Durga Puja pandal in Jabalpur district. The incident occurred on September 24 when the children came into contact with an iron pipe that had been negligently wired with electricity by the pandal organisers.

The media report, published on September 25, prompted the NHRC to intervene.

The Commission has issued notices to the Chief Secretary of Madhya Pradesh and the Superintendent of Police, Jabalpur, demanding a detailed report on the circumstances leading to the deaths and the status of the investigation.

A three-member inquiry team led by a Sub Divisional Magistrate (SDM) has reportedly been formed to probe the matter.

Both incidents have sparked outrage and underline the urgent need for stronger child protection mechanisms, public awareness, and accountability.

The NHRC’s intervention signals a call for systemic reform and justice for the victims, as Madhya Pradesh grapples with the dual challenge of combating superstition and ensuring safety in public spaces.

LATESTLY, Online, 8.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

LatestLY

# Children Branded With Hot Iron Rod in Madhya Pradesh: NHRC India Takes Suo Motu Cognizance of Branding of 3 Children by Faith Healer in Jhabua

The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken suo motu cognisance of a media report that three children suffering from pneumonia were branded with a hot iron rod by a faith healer in Jhabua district of Madhya Pradesh.

https://www.latestly.com/agency-news/children-branded-with-hot-iron-rod-in-madhya-pradesh-nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-branding-of-3-children-by-faith-healer-in-jhabua-7147134.html

Agency News ANI| Oct 07, 2025 02:33 PM IST

New Delhi, October 7: The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken suo motu cognisance of a media report that three children suffering from pneumonia were branded with a hot iron rod by a faith healer in Jhabua district of Madhya Pradesh. According to the statement, the condition of one of the children is severe. The doctors have confirmed that the victims were suffering from pneumonia, and there were burn marks on their bodies.

The statement said that the Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious concerns about potential human rights violations. Therefore, it has issued notices to the District Magistrate and the Superintendent of Police, Jhabua, calling for a detailed report on the matter within two weeks. On September 25, the parents of the children reportedly took the ailing children to the faith healer.

(The above story is verified and authored by ANI staff, ANI is South Asia's leading multimedia news agency with over 100 bureaus in India, South Asia and across the globe. ANI brings the latest news on Politics and Current Affairs in India & around the World, Sports, Health, Fitness, Entertainment, & News. The views appearing in the above post do not reflect the opinions of LatestLY)

TV9 Hindi

## Jhabua: निमोनिया खत्म करने के लिए दो महीने के बच्चों को गर्म सलाखों से दागा, ऑक्सीजन सपोर्ट पर मासूम

मध्य प्रदेश के झाबुआ में अंधविश्वास के नाम पर तीन बीमार बच्चों को इलाज की जगह गर्म लोहे से दाग दिया गया. तीनों बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है.

https://www.tv9hindi.com/state/madhya-pradesh/jhabua-three-children-branded-with-iron-rod-name-of-pneumonia-treatment-nhrc-suo-motu-cognizance-3515078.html

शुभम गुप्ता | Updated on: Oct 07, 2025 10:55 AM IST

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में अंधविश्वास के नाम पर मासूम बच्चों को इलाज की जगह गर्म सलाखों से दागने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. तीनों बच्चे निमोनिया से पीड़ित थे. इनमें से दो की उम्र मात्र दो महीने है और तीनों ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं. इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लिया है.

जानकारी के अनुसार, जिला अस्पताल के पीडियाट्रिशियन डॉ. संदीप चोपड़ा ने थाना प्रभारी को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है. तीनों बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान पता चला कि इन्हें अंधविश्वास में पड़कर लोहे की गर्म सलाखों से दाग दिया गया है. तीन बच्चों में दो बच्चों की उम्र महज दो महीने हैं, जबकि तीसरी बच्ची छह महीने की है. तीनों की हालात गंभीर बनी है. उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है.

### तांत्रिक के कहने बर बच्चों को दागा

निमोनिया होने के बाद परिजनों ने अंधविश्वास में आकर गांव के एक तांत्रिक के कहने पर अपने ही बच्चों के शरीर पर गर्म सलाखों से दाग दिया. पहली बच्ची, जिसकी उम्र सिर्फ दो महीने है, उसका पूरा इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा था, लेकिन इलाज के बीच उसकी गर्दन और पेट पर लकड़ी या लोहे की गर्म छड़ों से कई जगह जले हुए घाव बना दिए गए. दूसरी घटना भी एक दो महीने के मासूम से जुड़ी है, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर ऑक्सीजन पर रखकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके नन्हे बदन पर पेट के पास तीन गहरे दाग मिले.

### डॉक्टर की शिकायत पर दर्ज हुआ केस

तीसरी, छह महीने की बच्ची के पेट के दोनों ओर और पीठ के हिस्से पर दागने के ताजा निशान हैं, और वह भी अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से कराह रही है. इन बच्चों की चीखें और उनकी मांओं की बेबसी झाबुआ जिले के हर नागरिक का दिल दहला देती हैं. डॉक्टर और स्वास्थ्य अमला इस घटना से स्तब्ध हैं. जिला अस्पताल के पीडियाट्रिक इंचार्ज डॉ. संदीप चोपड़ा ने पूरे मामले की जानकारी थाना प्रभारी को लिखित में दी और जोर देकर कहा कि ऐसा इलाज अमानवीय और खतरनाक है.

2023 में भी झाबुआ जिले में इसी तरह की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने कड़ी कार्रवाई की थी. रिपोर्ट तलब कर दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी. बावजूद इसके, एक बार फिर झाबुआ में अंधविश्वास ने मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है. डॉक्टरों ने साफ कहा है कि निमोनिया या ऐसे संक्रमण का इलाज

सिर्फ अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में किया जाना चाहिए, अंधविश्वास से तो मासूम की जान तक जा सकती है.

NHRC ने लिया मामले पर संज्ञान

प्रशासन और पुलिस सक्रिय हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक बच्चों को अंधविश्वास की यह जलती सजा दी जाती रहेगी? इस मामले में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया है. एनएचआरसी ने इस गंभीर मामले पर आयोग ने झाबुआ के कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी किया है. साथ ही दोनों अधिकारियों से दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

ASIANET NEWS HINDI, Online, 8.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Asianet News Hindi

# अंधविश्वास की इंतहा : 2 महीने के मासूम को गर्म सलाखों से दागा गया! जानिए क्यों?

https://hindi.asianetnews.com/state/madhya-pradesh/madhya-pradesh-jhabua-babies-burned-hot-iron-pneumonia-nhrc/articleshow-no520i2

3 Min read

Surya Prakash Tripathi

Published : Oct 07 2025, 12:06 PM IST

मध्य प्रदेश झाबुआ में अंधविश्वास के नाम पर तीन मासूम बच्चों को गर्म सलाखों से दागा गया। सभी गंभीर हालत में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। NHRC ने स्वतः संज्ञान लेकर कलेक्टर और SP से रिपोर्ट मांगी।

Jhabua Babies Burned: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में अंधविश्वास के नाम पर तीन मासूम बच्चों के साथ बेहद शर्मनाक और खतरनाक घटना सामने आई है। बच्चों का इलाज करने की बजाय, परिजनों ने तांत्रिक के कहने पर गर्म सलाखों से बच्चों को जला दिया। यह अमानवीय कार्य निमोनिया से पीड़ित बच्चों पर किया गया और सभी बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लिया है।

अंधविश्वास या इलाज-बच्चों के साथ क्यों हुआ ऐसा?

तीनों बच्चों में दो की उम्र मात्र दो महीने है और तीसरी बच्ची छह महीने की है। जानकारी के अनुसार, बच्चों को गांव के एक तांत्रिक के कहने पर गर्म लोहे की छड़ से जला दिया गया। पहली बच्ची, जिसकी उम्र सिर्फ दो महीने है, का इलाज अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा था, लेकिन उसकी गर्दन और पेट पर कई जगह घाव बने। दूसरे बच्चे के पेट पर तीन गहरे दाग हैं, जबकि तीसरी बच्ची के पेट और पीठ पर हाल ही में दाग के निशान पाए गए। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे इलाज से बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है।

क्या अंधविश्वास मासूमों के लिए खतरा बन गया है?

झाबुआ में यह घटना 2023 में भी हुई थी, जब बच्चों को इसी तरह से गर्म सलाखों से दागा गया था। उस समय NHRC ने कड़ी कार्रवाई की थी और दोषियों की गिरफ्तारी हुई थी। बावजूद इसके, अब फिर से अंधविश्वास ने मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया।

NHRC और प्रशासन की प्रतिक्रिया-क्या कार्रवाई होगी?

इस गंभीर मामले पर NHRC ने झाबुआ के कलेक्टर और SP को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि निमोनिया या अन्य संक्रमण का इलाज केवल डॉक्टरों की देखरेख में ही होना चाहिए, अंधविश्वास बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है।

ऑक्सीजन सपोर्ट पर मासूम-क्या उनकी जान बच पाएगी?

तीनों बच्चे वर्तमान में अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की जान बच सके। परिजनों की लापरवाही और अंधविश्वास के चलते बच्चों को हुए नुकसान ने पूरे जिले में चिंता और डर का माहौल पैदा कर दिया है।

क्या झाबुआ में अंधविश्वास पर लगाम लगाई जाएगी?

यह घटना केवल झाबुआ की ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की शर्मनाक हकीकत को उजागर करती है। अंधविश्वास और तांत्रिकों के गलत प्रभाव ने मासूम बच्चों की जिंदगी पर खतरा डाल दिया है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और समाज मिलकर इस बुराई को रोक पाएंगे?

Orissa Diary

## NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of a 5-year-old student due to alleged beating by a teacher at a residential school, Hazaribagh, Jharkhand

https://orissadiary.com/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-death-of-a-5-year-old-student-due-to-alleged-beating-by-a-teacher-at-a-residential-school-hazaribagh-jharkhand/

By:Odisha Diary Bureau | Date: October 7, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance a media report that a 5-year-old student at a residential school in Hazaribagh district of Jharkhand succumbed to his injuries sustained in the severe beating by a teacher on 24th September, 2025. Reportedly, the brother of the deceased child, who is also a student at the same school, disclosed that the teacher assaulted his brother when he refused to consume the food.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of human rights violation. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of Jharkhand and the Superintendent of Police, Hazaribagh, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report carried out on 25thSeptember, 2025, the erring teacher and the manager of the school are absconding.

India Education Diary

# NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of a 5-year-old student due to alleged beating by a teacher at a residential school, Hazaribagh, Jharkhand

https://indiaeducationdiary.in/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-death-of-a-5-year-old-student-due-to-alleged-beating-by-a-teacher-at-a-residential-school-hazaribagh-jharkhand/

By iednewsdesk | October 7, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance a media report that a 5-year-old student at a residential school in Hazaribagh district of Jharkhand succumbed to his injuries sustained in the severe beating by a teacher on 24th September, 2025. Reportedly, the brother of the deceased child, who is also a student at the same school, disclosed that the teacher assaulted his brother when he refused to consume the food.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of human rights violation. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary, Government of Jharkhand and the Superintendent of Police, Hazaribagh, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

According to the media report carried out on 25thSeptember, 2025, the erring teacher and the manager of the school are absconding.

Indian Mandarins

## Appointments & Recommendations (GoI):- 06.10.2025

https://www.indianmandarins.com/news/appointments-recommendations-goi-06-10-2025/31517

By IndianMandarins- 21 hrs

New Delhi (06.10.2025): Notifications of appointments and recommendations issued on Monday are as follows:

Sandeep Ahuja (IRS IT: 2015) has been appointed as Officer on Special Duty to the Minister of State for Commerce & Industry and Electronics & Information Technology Jitin Prasada in the Ministry of Commerce & Industry at the level of Deputy Secretary for a period of four years.

Tenure of Dharmendra Kumar Singh (IA&AS: 2000), Joint Secretary, Department of Defence, has been extended for a period up to 31.03.2026.

Gaurav Garg (IPS: 2011: PB), Passport Officer under Ministry of External Affairs, has been appointed as Deputy Inspector General in National Human Rights Commission (NHRC) up to 15.11.2027.

Nilabhra Sengupta (IRSSE: 1997), CVO, Bharat Electronics Ltd. (BEL), Bengaluru, has been prematurely repatriated to his parent cadre with the condition of extended 'cooling-off.

Indian Masterminds

## IRS Sandeep Ahuja Named OSD to Jitin Prasada; IAAS Dharmendra Singh Gets Defence Extension; IPS Gaurav Garg Appointed DIG in NHRC

https://indianmasterminds.com/news/sandeep-ahuja-osd-jitin-prasada-dharmendra-singh-defence-gaurav-garg-nhrc-150235/

Bureaucratic Shuffle: IRS, IA&AS, and IPS Officers Get New Roles in Strategic Ministries

Indian Masterminds Bureau

October 7, 2025

New Delhi: The Government of India has issued fresh appointment and extension orders for senior civil servants across key ministries, as per notifications released by the Department of Personnel and Training (DoPT) on Monday.

The Appointments Committee of the Cabinet (ACC) approved the following postings and tenure extensions in a series of decisions that impact the Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Defence, and the National Human Rights Commission (NHRC).

Sandeep Ahuja Appointed OSD to MoS Jitin Prasada

In a notable appointment, Mr Ahuja (IRS-IT: 2015) has been designated as Officer on Special Duty (OSD) to Jitin Prasada, Minister of State for Commerce & Industry and Electronics & Information Technology.

Position Level: Deputy Secretary

Tenure: Four years, starting from the date of assumption of charge

Conditions: Co-terminus with the Minister’s tenure or until further orders

The appointment places Ahuja in a pivotal support role to MoS Jitin Prasada at a time when both commerce and digital governance sectors are witnessing accelerated reforms and policy thrust.

Dharmendra Kumar Singh Gets Second Extension as Defence Joint Secretary

Mr Singh (IA&AS: 2000), serving as Joint Secretary in the Ministry of Defence since August 2022, has received a six-month extension to his central deputation.

New Tenure Validity: Up to March 31, 2026, or until further orders

Previous Extension: March 19, 2025 – September 30, 2025

This marks Singh’s second extension, signaling continuity in senior leadership at the Defence Ministry during a critical time for defence modernization and strategic planning.

Gaurav Garg Appointed DIG in NHRC

Mr Garg (IPS: 2011: PB), currently serving as Passport Officer under the Ministry of External Affairs, has been appointed as Deputy Inspector General (DIG) in the National Human Rights Commission (NHRC).

Tenure: Till November 15, 2027

New Role: Key position in India's apex human rights body

His posting to NHRC comes at a time when the Commission is increasingly engaged in addressing high-profile human rights issues, both domestic and international.

Tribune

# NGO urges Delhi Govt to expedite winter action plan amid forecast of severe cold

Asks shelter board to activate night shelters, ensure adequate blankets

https://www.tribuneindia.com/news/delhi/ngo-urges-delhi-govt-to-expedite-winter-action-plan-amid-forecast-of-severe-cold/amp

Anshita Mehra

Tribune News Service

New Delhi, Updated At : 05:24 AM Oct 08, 2025 IST

With weather agencies warning of an early and harsh winter due to the La Nina effect, a Delhi-based NGO, the Centre for Holistic Development (CHD), has written to Chief Minister Rekha Gupta and senior Delhi Government officials, urging immediate implementation of the Winter Action Plan 2025-26 to protect the city's homeless population.

In a letter addressed to the CM, Lt. Governor Vinai Kumar Saxena, Commissioner of Police, Chief Secretary, Chief Executive Officer (CEO) of Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) and the Secretary General of the National Human Rights Commission (NHRC), Chandigarh executive director Sunil Kumar Aledia highlighted thousands of vulnerable individuals could be left exposed to life-threatening cold if the plan is not advanced ahead of the scheduled date (November 15).

"Given the high likelihood of harsh weather conditions arriving earlier than usual, the current timeline risks leaving thousands of vulnerable individuals unprotected during the crucial early weeks of the season," the letter stated.

The NGO urged DUSIB to activate night shelters, ensure adequate blankets, warm clothing and heating facilities and deploy outreach and rescue teams to identify and relocate homeless individuals before temperatures drop further. To strengthen preparedness, Chandigarh proposed expanding shelter management and rescue teams, improving the 24×7 monitoring system and control room, updating the Delhi Shelter Board mobile app and ensuring timely repair and maintenance of existing shelters.

According to the latest DUSIB occupancy report, out of 325 shelter homes, 82 are in RCC buildings, 103 in porta cabins, 10 under special drives, 8 in temporary buildings and 122 in tents.

Earlier this year, Chandigarh had reported that 474 homeless people died in the National Capital between November 15, 2024 and January 10, 2025, during the peak of the winter season. The NGO claimed the absence of official data obscures the true scale of the crisis, estimating that around 80 per cent of "unidentified dead bodies" in Delhi are those of homeless individuals, based on police data.

The NHRC had subsequently taken suo motu cognizance of the reported deaths and issued notices to the Chief Secretary and Delhi Police Commissioner, seeking a detailed report within a week.

CHD's latest appeal stresses proactive steps now could save countless lives. "Delhi has the capacity and resources to ensure that no one dies due to cold on our streets," the letter said.

Times of India

# NHRC steps in after child deaths in MP

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/nhrc-steps-in-after-child-deaths-in-mp/articleshowprint/124371175.cms?val=3728

TNN | Oct 8, 2025, 12.45 AM IST

Bhopal: The National Human Rights Commission (NHRC) of India has taken suo motu cognisance of an incident where two children, aged 8 and 10 years, died due to electrocution while playing inside a Durga Puja pandal in Jabalpur district.

The commission on Monday stated that the incident reportedly occurred when the children came into contact with an iron pipe on Sept 24. The electric wires were connected negligently by the organisers of the pandal.

The commission observed that this raises serious issues of human rights violations. Therefore, it has issued notices to the chief secretary, govt of MP, and the superintendent of police, Jabalpur, calling for a detailed report on the matter within two weeks. It is expected to include the status of the investigation.

In a different incident, NHRC took suo motu cognisance of a case where three children suffering from pneumonia were branded with a hot iron rod by a faith healer in Jhabua district. The commission stated that reportedly the condition of one of the children is serious. The doctors confirmed that the children were suffering from pneumonia and there were burn marks on their bodies.

The commission observed that if true, the incident raises serious issues of human rights violations. Therefore, it has issued notices to the district magistrate and the superintendent of police, Jhabua, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

Kashmir Media Services

## Probe ordered into Muslim man’s custodial death in Maharashtra jail after five years

https://kmsnews.org/kms/2025/10/07/probe-ordered-into-muslim-mans-custodial-death-in-maharashtra-jail-after-five-years.html

October 7, 2025Last Updated: October 7, 2025

Nashik: India’s National Human Rights Commission (NHRC) has initiated a “spot investigation” into the 2020 custodial death of 31-year-old inmate Asghar Ali Mansoori at Nashik Central Jail in Maharashtra, five years after The Wire first uncovered the case. Mansoori died inside the prison, and a note retrieved from his stomach identified five jail officials whom he accused of torture and harassment.

According to Kashmir Media Service, Mansoori reportedly swallowed the note, wrapped in a polythene bag, before hanging himself from a ceiling fan during the COVID-19 lockdown on October 7, 2020. The note was later recovered from his stomach during the post-mortem but was never treated as a dying declaration. Despite the serious allegations, Maharashtra Police failed to initiate a criminal inquiry against the named officials, some of whom have since been transferred or retired.

The NHRC’s decision follows two formal complaints lodged after The Wire’s detailed report on the case. NHRC Deputy Superintendent of Police Dushyant Singh, who is leading the visit, said the delay was due to “non-cooperation from the state authorities,” adding that the Commission still hasn’t received the mandatory magisterial inquiry report.

Mansoori had been working as a warder inside the prison. In his note, he alleged that jail officials identified as Baviskar, Chavan, Sarpade, Gite, and Karkar subjected him to prolonged torture and solitary confinement for nearly a year. His father, Mumtaz Ali, has consistently disputed the official version of events and accused authorities of a cover-up.

Following the death, six fellow inmates wrote to the Chief Justice of the Bombay High Court detailing the abuse of prisoners at Nashik Central Jail, but no action was taken. Human rights activists Sanjoy Hazarika and Dhana Kumar later petitioned the NHRC, pressing for a probe under the Protection of Human Rights Act.

Lawyer Vijay Hiremath, representing Mansoori’s family, said the state was legally bound under Section 176(1A) of the Code of Criminal Procedure to conduct a judicial magistrate inquiry into custodial deaths but failed to share the report with the family or the court.

Prisoners’ rights activist Wahid Shaikh said Mansoori’s death “was a clear case of custodial torture and institutional neglect.” He added that despite the suicide note directly naming his abusers, “no accountability has been fixed even after five years.”

Several inmates who corroborated Mansoori's allegations later reported facing threats and physical abuse. One prisoner, who testified to the torture and named the same officials, was transferred to Nagpur Prison after being beaten.

MAKTOOBMEDIA, Online, 8.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Maktoob Media

## Arunachal Pradesh-based lawyer Ebo Mili stopped at Kolkata airport over lookout notice

https://maktoobmedia.com/india/arunachal-pradesh-based-lawyer-ebo-mili-stopped-at-kolkata-airport-over-lookout-notice/

Nikita Jain | October 7, 2025

Modified : October 7, 2025

In what many are calling a blatant attack on dissenting voices, Arunachal Pradesh-based human rights lawyer and environmental activist Ebo Mili was prevented from boarding a flight to Dhaka from Kolkata airport on Saturday due to a lookout notice issued by the state police.

Mili was scheduled to attend the Regional Infrastructure Monitoring Alliance (RIMA) conference in Dhaka from October 5 to 7.

Speaking to Maktoob, Mili said that there was no need for the Arunachal Pradesh Police to issue such an order.

“This is harassment, a misuse of power. We are being targeted for advocating against the Siang dam. I won’t be surprised if next they arrest us under the National Security Act. There are so many ministers with actual crimes, yet they go overseas; rapists and murderers get parole, while people who are actually working for their land and environmental protection are being tagged as anti-national,” he told Maktoob.

Mili is the second activist to be stopped from going abroad over a lookout notice.

In early September, noted environmental activist Bhanu Tatak was stopped at Delhi airport when she was travelling to Ireland.

She was stopped by the immigration authorities from travelling abroad on the basis of a lookout circular issued by the Arunachal Pradesh Police, officials had said.

The activists were stopped on the basis of complaints whose details have not been shared, but many assume it is for protesting against the proposed mega dam on the Siang River.

Since reports of the dam were released, intense opposition has sparked a chain of protests against other hydropower projects in Arunachal Pradesh.

Civil society members are alleging that the proposed project is illegal as the mandatory free, prior, and informed consent was not obtained from the Gram Sabhas in many cases — a common pattern observed in such projects.

The government’s push towards the mega hydropower project on the Siang River reportedly aims to curb perceived threats from China.

In June, the National Human Rights Commission (NHRC) took suo motu cognizance of a media report that residents were opposing the proposed construction of a dam, apprehending that it may result in the displacement of several people and adversely impact livelihoods and ecology in the Siang district.

Reportedly, to deal with the situation, the government has deployed central armed forces in various areas of the Siang district in the state.

The Commission observed that the contents of the news report, if true, raise issues of violation of human rights. Therefore, it issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Arunachal Pradesh, calling for a detailed report in the matter within two weeks.

On May 23, a human rights activist and convenor of the Siang Indigenous Farmers Forum also led a protest against the dam construction in Beging village, in which approximately 400 people participated.

Patrika

## मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो नहीं बख्शे जाएंगे अधिकारी: प्रियंक कानूनगो

https://www.patrika.com/videos/sagar-news/officials-will-not-be-spared-if-human-rights-are-violated-priyank-kanoongo-20005892

सागर • Rizwan ansari • Oct 07, 2025, मंगलवार

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो रविवार को सागर पहुंचे। प्रियंक कानूनगो ने शुक्रवारी-शनिचरी वार्ड में क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं सुनीं।

Lalluram

# मानव अधिकार आयोग के सदस्य से बदसलूकीः प्रियंक कानूनगो ने पूरी घटना को X पर किया पोस्ट

https://lalluram.com/human-rights-commission-member-manhandled-priyank-kanoongo-posted-the-entire-incident-on-x/

Satyanarayan Shukla | 07 Oct 2025, 12:39 PM

मध्यप्रदेश

कुमार इंदर, जबलपुर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो से बदसलूकी का मामला सामने आया है। थाने का रिकॉर्ड मांगने पर पुलिस वालों पर बदसलूकी का आरोप है। उन्होंने मामले को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

रिकॉर्ड मांगने पर सब इंस्पेक्टर ने नहीं दिया

प्रियंक कानूनगो ने घटना का विवरण X पर पोस्ट किया है। लिखा- मैं मध्यप्रदेश प्रवास के दौरान जबलपुर जिले के शहपुरा थाने पहुंचा। मैं हवालात इत्यादि के निरीक्षण के लिए आया था। यहां पुलिस स्टाफ मौजूद नहीं है केवल 2 पुलिस कांस्टेबल मिले। कोई स्टाफ या हवालात में बंदियों की गणना रिकॉर्ड नहीं मिला। रिकॉर्ड मांगने पर सब इंस्पेक्टर महेंद्र जाटव ने सहयोग करने से इंकार किया।

5 अक्टूबर को x पर किया पोस्ट

सब इंस्पेक्टर ने बिना पूर्व सूचना के थाने नहीं आ सकते की बात कही। ने DGP को टैग का पूछा हमको निरीक्षण की आज्ञा किससे लेनी होगी ? @MPPoliceDeptt के डीजीपी से पूछेंगे कि हमको निरीक्षण की आज्ञा किससे लेनी होगी ? @DGP_MP प्रियंक कानूनगो ने 5 अक्टूबर को x पर पोस्ट किया है।

AMAR UJALA, Online, 8.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Amar Ujala

## Chitrakoot News: अनुसूचित जाति जनजाति के पॉक्सो एक्ट के पीड़ितों को मिले मुआवजे का जाना हाल

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/chitrakoot/know-the-status-of-compensation-given-to-the-victims-of-pocso-act-of-scheduled-castes-and-tribes-chitrakoot-news-c-215-1-sknp1043-121771-2025-10-08

संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 08 Oct 2025 12:33 AM IST

चित्रकूट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में मानवाधिकार एवं समावेशी विकास की समीक्षा बैठक मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के पॉक्सो एक्ट के पीड़ितों को मुआवजा मिलने की जानकारी ली। वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धों से बातचीत में कहा कि उनके घर में भी उनका हिस्सा है, लेकिन उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

समीक्षा बैठक में सदस्य ने समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर व मेडिकल पर एवं 25 प्रतिशत चार्जशीट पर दिया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि जनपद में कितने आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित है जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 24 हजार का लक्ष्य दिया गया है जिसमें लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 22 हजार आयुष्मान कार्ड बना दिया गया है। उन्होंने वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित कितने व्यक्ति हैं जानकारी लिए और कहां की कोई भी लाभार्थी छूटने न पाए।

उन्होंने नगर पालिका परिषद कर्वी के संबंध में सफाई कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जिला दिव्यांग अधिकारी कहा कि कोई भी दिव्यांग छूटने न पाए कहा कि सरकार द्वारा जो योजनाएं आती है उसके बारे में भी कैंप लगाकर बताएं । नाबालिग बच्चे कार्य स्थल पर कार्य करते हुए पाए जाते हैं तो ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं ।अगर नहीं होता है तो पुलिस अधीक्षक से बताएं तभी ठेकेदारों का होश ठिकाने होगा। इस मौके पर सीडीओ अमृतपाल कौर, एसपी अरुण कुमार सिंह समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे।

HINDUSTAN, Online, 8.10.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Hindustan

# जनसुनवाई करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/kausambi/story-national-human-rights-commission-member-priyanka-kanungo-to-visit-manjhanpur-for-public-hearing-201759855081625.amp.html

Tue, 7 Oct 2025, 10:08:PM

Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बी

Kausambi News - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य प्रियांक कानूनगो 8 अक्तूबर को मंझनपुर आएंगी। वह 12 बजे आमजन एवं स्थानीय सिलिकोसिस रोगियों की जनसुनवाई करेंगी। इसके बाद 2 बजे संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक...

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियांक कानूनगो आठ अक्तूबर को दोपहर 12 बजे मंझनपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वह दो बजे तक विकास भवन स्थित सरस हाल में आमजन एवं स्थानीय सिलिकोसिस रोगियों की जनसुनवाई करेंगे। अपरान्ह दो बजे से उदयन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद शाम चार बजे जनपद से प्रस्थान करेंगे।

Lucknow Tribune

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में 'यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH – Prevention of Sexual Harrasment)' पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

https://thelucknowtribune.com/babasaheb-bhimrao-ambedkar-university-organized-the-prevention-of-sexual-harassment-in-posh-prevention-of-sexual-harrasment-awareness-program-organized-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE/

October 7, 2025 TLT Desk 9 Views

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में दिनांक 6 अक्टूबर को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की ओर से 'यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH- Prevention of Sexual Harrasment)' विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉ. आशिमा मंगला ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी। इसके अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी एवं आंतरिक शिकायत समिति, बीबीएयू की अध्यक्ष प्रो. आभा मिश्रा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं बाबासाहेब के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। विश्वविद्यालय कुलगीत गायन के पश्चात आयोजन समिति की ओर से अतिथियों एवं शिक्षकों को पौधा, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। सर्वप्रथम प्रो. आभा मिश्रा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया एवं सभी को कार्यक्रम के उद्देश्य एवं रुपरेखा से अवगत कराया।

विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में लोग अपने साथ हुए अपराधों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और निडर होकर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कि अत्यंत सराहनीय पहल है। साथ ही जब समाज के सभी वर्ग मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। इस अवसर पर उन्होंने 'विशाखा गाइडलाइन्स' का उल्लेख करते हुए बताया कि इन दिशा-निर्देशों ने महिलाओं को अपनी आवाज़ बुलंद करने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का एक सशक्त मंच प्रदान किया है। प्रो. मित्तल ने आगे कहा कि आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसर को सुरक्षित, संवेदनशील और लैंगिक समानता पर आधारित वातावरण प्रदान करना है। यह समिति प्रत्येक शिकायत को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और सक्रियता के साथ सुनती है तथा निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है, जिससे आपसी विश्वास और सम्मान का वातावरण बन सके। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक परिसरों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक जागरूकता एवं सहयोग ही एक समग्र समाधान है।

विशिष्ट अतिथि एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आंतरिक शिकायत समिति की प्रमुख जिम्मेदारी विश्वविद्यालय परिसर को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थान केवल ज्ञान का केंद्र नहीं होते, बल्कि यह विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देने का कार्य भी करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी 'विशाखा गाइडलाइन्स' ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन

उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक ऐतिहासिक दिशा दी। इन गाइडलाइन्स ने संस्थानों को यह बाध्य किया कि वे ऐसी समितियाँ गठित करें जो शिकायतों की जांच करें, पीड़ित को सहयोग प्रदान करें और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान में ICC की स्थापना न केवल शिकायतों के निवारण का माध्यम है, बल्कि जागरूकता, संवाद और विश्वास की संस्कृति को भी बढ़ावा देती है। श्रीमती सयानी ने विभिन्न केस स्टडीज़ के उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे कई महिलाओं ने साहस दिखाते हुए अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, जिससे अन्य पीड़ितों को भी प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भी इस दिशा में विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करता है और मानवाधिकारों से जुड़ी संवेदनशीलता को शैक्षणिक परिसरों में मजबूत करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बनाये गये यूजीसी विनियम 2015, शून्य सहिष्णुता नीति (Zero Tolerance Policy) आदि की विस्तृत जानकारी दी।

यूजीसी ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉ. आशिमा मंगला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए हैं। UGC ने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की स्थापना अनिवार्य की है, ताकि किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का शीघ्र और निष्पक्ष समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि UGC के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी पीड़ित महिला तीन माह के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और आवश्यक होने पर उसके परिवार का कोई सदस्य भी यह शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही विश्वविद्यालयों में लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, जागरूकता अभियान, शिकायत पेटी और हेल्पलाइन नंबर जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य की गई हैं। डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए आयोग ने 'सक्षम पोर्टल' (SAKSHAM Portal) की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से छात्राएँ एवं महिलाएँ अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकती हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो गई है।

कार्यक्रम के दौरान कुलपति जी एवं अतिथियों द्वारा आईसीसी द्वारा तैयार 'पॉथवे टू सेफ कैंपस' शीर्षक पर आधारित हैंडबुक का विमोचन किया गया। साथ ही आईसीसी द्वारा आयोजित स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों ने आईसीसी (Internal Complaints Committee), पॉश अधिनियम (POSH Act) एवं महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर अतिथियों द्वारा अत्यंत संतोषजनक एवं विस्तारपूर्वक दिया गया। अतिथियों ने न केवल प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया, बल्कि उन्हें संबंधित नियमों, शिकायत प्रक्रिया तथा विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्ध सहायता तंत्र की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की।

इस अवसर पर शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए तो विशेष व्याख्यान सत्रों का आयोजन किया गया। प्रथम व्याख्यान सत्र उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ. वी.के. सिंह की अध्यक्षता में 'यूजीसी विनियम 2013 बनाम यूजीसी विनियम 2015 (उच्च शिक्षण संस्थानों – HEIs) लिंग आधारित विशेषताओं सहित' विषय पर आयोजित किया गया। द्वितीय व्याख्यान सत्र मनोचिकित्सक डॉ. शाजिया सिद्दीकी की अध्यक्षता में 'यौन उत्पीड़न का मनोवैज्ञानिक प्रभाव: साधन, सहायता और संसाधन' विषय पर आयोजित हुआ।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और कैंपस में संवेदनशीलता पैदा करने के उद्देश्य से एक मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को लैंगिक समानता, सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।

अंत में डॉ. दीपा राज ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समस्त कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, कर्मचारी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।